

[Shri T. A. Pai]

that they will take all these factors into consideration and take whatever action is necessary.

So far as the decasualisation of labour is concerned, the hon. Member knows that even in the steel industry, a series of discussions are being undertaken between the management and the union to categorise the various types of functions and to find out which of them are perennial and which of them are of a casual nature, so that an early decision might be arrived at on decasualising labour. I have told the same thing to the Wage Negotiating Committee and the Coal Ministry also, that they might continue these discussions to find out how many of this casual labour can be absorbed permanently. The hon. Member has already conceded that it may not be possible to take all the 20,000. So, certainly, even if a large number is left out, I hope that with the development of the coal industry we are now taking on hand, most of them would be able to find enough employment.

**SHRI C. K. CHANDRAPPA:** What about having discussions with the representatives of the trade union before the strike commences?

**SHRI T. A. PAI:** I shall certainly be happy to meet the trade unions and find out what exactly the strike is about, and try to see that an agreement is reached with them.

**MR. SPEAKER:** Shri B. N. Reddy—absent; Shri Nawal Kishore Sinha—absent; Shri Shrikishan Modi—absent. So, the Calling Attention is over.

12.33 hrs.

#### QUESTION OF PRIVILEGE

PRESS STATEMENT ISSUED BY SECRETARY,  
J. K. ORGANISATION

**MR. SPEAKER:** Shri Madhu Limaye had sought to raise a question

of privilege on the 5th September, 1973, against the "J. K. Organisation" in respect of a Press statement issued by the Secretary, J. K. Organisation, Kanpur and published in the *Hindustan Times*, dated the 1st September, 1973.

Shri Madhu Limaye, while raising the matter in the House, stated *inter alia* that he had never mentioned the "J. K. Organisation" at all in Lok Sabha but only mentioned companies belonging to the "J. K. Group". Shri Limaye had alleged that by publishing that Press statement, the J. K. Organisation had not only made a misleading statement but also cast reflections on him.

I had then said that I would first get the comments of the J. K. Organisation.

The Secretary, J. K. Organisation, Kanpur, who was accordingly asked under my direction to state what he might have to say in the matter, in his reply dated the 17th October, 1973, stated *inter alia* that he had issued the impugned Press statement on the basis of a news item published in the *National Herald*, dated the 25th August, 1973. He also stated:—

"...It now appears that the Press Note published in the *National Herald* was incorrect and misleading... Like everyone else, I assumed the news item in the *National Herald* to be correct version of what Shri Limaye had said in the House and proceeded on that basis... The Press statement was issued by me in the honest and bonafide belief, that the news item published in the *National Herald* was correct."

"In the end I would, on behalf of the J. K. Organisation again like to express regret in case any inconvenience or misunderstanding has been caused to Shri Limaye as regards this matter. I would like to

assure him that the press statement was issued in good faith for the protection of the reputation of the J. K. Organisation without any intention of affecting in any way the image and reputation of Shri Limaye and without the least idea that it will in any way involve any question of privilege."

In view of the explanation and regret expressed by the Secretary, J. K. Organisation, the matter may be treated as closed.

**श्री मधु लिमये (बांका) :** अध्यक्ष महोदय, आप जो निर्णय करना चाहते हैं वह आप कर सकते हैं। उस के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन जितना ये लोग अपने को मासूम और निष्पाप बता रहे हैं वैसी बात नहीं है। क्या कि नेशनल हेरल्ड का जो इन्होंने कटिंग दिया है जो टाइप-रिटेन है उस में जे के आर्गोनाइजेशन, 'ओ' मोटे अक्षर में कैपिटल में दिया है। नेशनल हेरल्ड का कटिंग देखें उस में 'ओ' कैपिटल में नहीं है। तो नेशनल हेरल्ड के संवाददाता ने गलती से ग्रुप की जगह पर आर्गोनाइजेशन शब्द इस्तेमाल किया है। उस को पता नहीं था कि इस तरह का एक संगठन है और पता चला है कि ट्रेड यूनियन ऐक्ट में यह रजिस्टर हो गया है। कैसे हुआ यह कमलापति जी बता सकते हैं। लेकिन यह भी एक रहस्य है। अगर केवल इस के बारे में जो नेशनल हेरल्ड में आया था उसी का इन को प्रतिवाद करना था तो जो बयान दिया है उस में ये दो पैराग्राफ इन्होंने क्यों जोड़े हैं, उन की ओर मैं आरा का ध्यान दिलाना चाहता हूँ :

"At times the banks unilaterally makes debits to the account of the

constituents which information is passed on to them very late. Cheques are drawn on banks based on the account appearing in the books of the constituents from day to day. Due to this reason if any cheques remain unpaid, they are paid subsequently by replenishing the banks account immediately on receipt of information from the bank."

अध्यक्ष महोदय, जब इन का कोई साता नहीं था, जब इन के बारे में मैं ने कुछ कहा नहीं था और वह कहते हैं कि हमारा कोई खाता नहीं है बैंक आफ बड़ौदा में और हमारा कोई चेक नहीं लौटाया गया, नहीं बाउंड हुआ तो जिन के चेक्स बाउंड हुए उन की सफाई ये क्यों देते हैं? आखिर जे के आर्गोनाइजेशन जो ट्रेड यूनियन ऐक्ट के तहत रजिस्टर हुआ है वह उन्हीं लोगों से संबंधित है और उन्हीं कंपनियों का एक आर्गोनाइजेशन है। यह उन्होंने स्वयं अपनी चिट्ठी में लिखा है। और उन कंपनियों के चेक बाउंड हुए हैं। आम जनता बोड़े ही फर्क जानती है कि जे के आर्गोनाइजेशन और जे के कंपनियों क्या हैं? इसके लिए क्या इन का इतना खुलासा काफी नहीं था कि हमारा कोई खाता नहीं था, हमारा कोई चेक बाउंड नहीं हुआ था और नेशनल हेरल्ड में जो खबर आई है वह गलत है? और सारे अखबारों को यह प्रेस स्टेटमेंट देने का क्या कारण था? नेशनल हेरल्ड के संपादक चेलापति राव को ये पत्र लिखते तो निश्चित रूप से, मैं राव साहब को जानता हूँ, वह खुलासा जरूर प्रकाशित करते। लेकिन उन्होंने जनरल प्रेस स्टेटमेंट दिया तो बाहर वाले लोग क्या समझे?

मेरे पास कई फोन काल आए हैं।

इसलिए अगर आप इन को माफ करन

[श्री मधु लिमये]

चाहते हैं तो करिए, मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन इन के जो ये दो पैराग्राफ हैं जिस में जिन जे के कम्पनियों के चेक वाउंड हो गए थे उन की एक माने में सफाई देने का उन्होंने प्रयास किया है, जब जे के कम्पनियों से उनका संबंध ही नहीं था तो सफाई ये क्यों कर रहे हैं ? जे के कम्पनियों क्यों नहीं कर रही हैं ? आज चव्हाण साहब इस का जवाब देकर चेक वाउंड होने के बारे में, 8 महीने में 71 चेक इन के वाउंड हुए थे और यह बिलकुल सही बात है, चव्हाण साहब ने इस का कोई प्रतिवाद नहीं किया है। तो ऐसी हालत में आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। वैसे आप का जो निर्णय हो वह आप कर सकते हैं। इस में मुझे बड़ी चालाकी नजर आ रही है। आप को इनको थोड़ा बहुत तो फटकारना चाहिए। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आप इस को कमेटी में भेजिए। लेकिन यह जरूर पृष्ठिए कि जब आप का कोई खाता ही नहीं था बैंक आफ बड़ौदा में और आप का कोई चेक वाउंड नहीं हुआ था तो जिन के चेक वाउंड हुए हैं उन की सफाई आप ने क्यों दी ? यह इतना मैं जानना चाहता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय :** देखिए, जो कुछ भी हुआ, उन्होंने अनक्वालीफाइड माफी मांग ली है....

**श्री मधु लिमये :** काहे की माफी मांगी है। उन्होंने जो वयान दिया है, उस के लिये उन को कोई सदमा नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय :** आप क्या चाहते हैं ?

**श्री मधु लिमये :** आप उन को लिखिये कि वे दो पैराग्राफ उन्होंने उस में क्यों डाले हैं ? चूंकि उन को खेद नहीं था, इसी लिये उन्होंने उस का खुलामा किया। इस के बाद आप जो निर्णय करना चहें, करें। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप इस को कमेटी में भेजिये, लेकिन इस तरह से इन मोनोपोलिस्ट्स को छोड़ें तो वे हम पर हावी हो जायेंगे।

**SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour):** There is some substance in what Shri Madhu Limaye has said.

**MR. SPEAKER:** I have laid it before the House. I think we should accept it. But, at the same time, I will convey that this part, which is brought to our notice by Shri Madhu Limaye, is also there which is highly regrettable. I think we should drop this.

**MR. SPEAKER:** I will now pass on to the next item.

**SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour):** I want to make a submission that the House should note that the people of West Bengal have protested against the economic policies of the Government, which have resulted in scarcity of goods and the consequent misery to the common toiling masses of the country. There was a complete bandh on the 17th and all the offices, including governmental institutions, were completely closed. It is a very serious matter. Because of the wrong economic policies formulated by the Central Government, there was scarcity in the supply of food, which is also controlled by the Centre. We want the House and the people to take note of this.